>

Title: Need to take necessary action on the proposal of Government of Uttar Pradesh regarding inclusion of backward castes of Uttar Pradesh in the list of Scheduled Castes.

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था। पर उन जातियों को अनुसूचित जाति में केन्द्र सरकार की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह उन जातियों के साथ न्याय नहीं है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार पुनः एक सूची केन्द्र को विधिवत उन जातियों के बारे में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अध्ययन करवाकर अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजी है।

मैं सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की जिन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव लंबित है, उनमें से कई किसी न किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति में हैं पर केन्द्र सरकार ने इस मामले में अभी तक आवश्यक कार्यवाही नहीं की है।

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर उन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें जिससे वे अनुसूचित जाति को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाकर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से ऊपर आ सकें।